आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 02.02.2026 समय : 0705

<><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्रीय बजट मानव–केंद्रित है और अभूतपूर्व सुधारों के साथ भारत की नींव को मजबूत करता है।
- विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने लोगों से आर्द्रभूमि का संरक्षण करने की अपील की है।
- सांसद बिष्णु पद रे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुनामी प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजे का अनुरोध किया है।
- पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय और कानूनी जानकारी देने के लिए ''खरीद मानदंड, बजट और लेखांकन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट मानव–केंद्रित है और अभूतपूर्व सुधारों के साथ भारत की नींव को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए देश के सुधार पथ तथा दीर्घकालिक विकास को गति देने वाला उत्प्रेरक करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में 2026–27 का आम बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बजट प्रस्ताव अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करेंगे, नागरिकों को सशक्त बनाएंगे और भारत के युवाओं को नई ऊंचाइयों को छूने के नए अवसर देंगे। सरकार के सुधार एजेंडे को "सुधार एक्सप्रेस" बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जिस सुधार एक्सप्रेस पर सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व सुधार महत्वाकांक्षी भारत के साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ान भरने के लिए खुला आसमान प्रदान करेंगे। वैश्विक मंच पर देश की महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आर्थिक और ऊपर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। श्री मोदी ने कहा कि उभरते क्षेत्रों, अवसंरचना और पूंजीगत व्यय को प्रमुखता से प्रोत्साहन दिया गया है और बजट में शामिल नई नीतिगत और व्यापारिक पहलों से युवाओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक अनूठा बजट है जो

राजकोषीय घाटे को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर केंद्रित होने के साथ ही उच्च पूंजीगत व्यय तथा उच्च विकास दर पर जोर देता है।

<><><><><><><><>

द्वीपसमूह में भी व्यवसायियों ने इस केन्द्रीय बजट का स्वागत किया है। बजट में द्वीपों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया है। इस संबंध में उद्योगपति मोहम्मद एच जाडवेट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट से द्वीपसमूह में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आने वाले समय में इस संबंधित सभी लोगों को लाभ होगा।

<><><><><><><><>

आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। इस अवसर पर उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने अपने संदेश में कहा कि आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए मौलिक और जीवन–निर्वाह के आधार हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के इस वर्ष का विषय "आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञानः सांस्कृतिक विरासत का उत्सव" है। यह विषय दुनिया भर के समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों के साथ आर्द्रभूमि के गहरे और स्थायी संबंधों पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह के लगभग छह प्रतिशत हिस्से को कवर करने वाली आर्द्रभूमियाँ, मानवता और अनगिनत प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये मत्स्य पालन, कृषि, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका का साधन है। इसके अलावा ये जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती हैं। उप–राज्यपाल ने लोगों से सामूहिक कल्याण और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण करने की अपील की है।

<><><><><><><><>

द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने सुनामी प्रभावित किसानों के मुआवजे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की अपील की है। अपने लिखे पत्र में सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री से उन किसानों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, जिनकी भूमि 2004 की विनाशकारी सुनामी के दौरान समुद्र में जलमग्न हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसान दो दशकों से अधिक समय से न्याय और मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं और बार–बार के प्रतिवेदनों और मांगों के बावजूद यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। सांसद ने गृह मंत्री से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक

प्रक्रिया शुरू करने और एक सकारात्मक तथा समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, ताकि लंबे समय से पीड़ित सुनामी प्रभावित किसानों को उनका उचित मुआवजा मिल सके।

<><><><><><><>

पंचायती राज संस्थाओं के लिए "खरीद मानदंड, बजट और लेखांकन" पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण स्थानीय शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय और कानूनी समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तकनीकी सत्र के दौरान अंडमान लोक निर्माण विभाग की वित्त अधिकारी के. चिंतामणि पंचायती राज संस्थाओं के लिए लागू खरीद मानदंड और वित्तीय नियम, बजट और लेखा, प्रमुख कानूनी प्रावधान तथा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीकों पर जानकारी दी।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह पंचायती राज संस्थानों का सहायता अनुदान, नियम, 2025 का मसौदा तैयार किया गया है। संबंधित हितधारकों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए मसौदे को विभाग और प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। दावे या आपत्तियां 30 दिनों के भीतर ग्रामीण विकास निदेशक के पास भेजे जा सकता है।

<><><><><><><>

एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल वीर सावरकर प्रेरणा पार्क में अंडमान चैप्टर के अध्यक्ष मोहन विनोद के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य साफ–सफाई, पर्यावरण की ज़िम्मेदारी और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष भूमिनाथन भी मौजूद थे। उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों को उनके भागीदारी, सहयोग और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में लगातार समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

<><><><><><><>

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने और स्टारगेजिंग गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले में रात के समय तारा दर्शन गतिविधियों के संचालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों, खगोल पर्यटन ऑपरेटरों

और आयोजकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन गतिविधियों के लिए प्रस्तावित स्थलों में करमाटांग समुद्र तट, रामनगर तट, बिडनाबाद, बर्मानाला, कोडियाघाट समुद्र तटीय क्षेत्र के अलावा वाइपर द्वीप शामिल है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खगोल पर्यटन को एक पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी गतिविधि के रूप में बढ़ावा देना है। इसके लिए इच्छुक आवेदक अपना लिखित आवेदन 10 फरवरी, तक सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में जमा कर सकते हैं।

<><><><><><><>